JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue

JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)

An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# बिहार एवं इसके पड़ोसी राज्यों में गरीबी की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण

दिव्या चन्द्रा* एवं स्वेता शरण**

* शोधार्थी, पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार

**सहायक प्राध्यापक, मगध महिला कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार

## सारांश

भारत के प्रमुख राज्यों में से बिहार एक है। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार राज्य के पूर्व में पश्चिम बंगाल , पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित है। इन तीन भारतीय राज्यों के अलावा बिहार के उत्तर में नेपाल है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार , बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 थी जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.58 प्रतिशत है। जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार , 2022 में अनुमानतः बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ होने की है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में तीसरा है। बहुआयामी सूचकांक के अनुसार , बिहार में 51.91 % व्यक्ति गरीब हैं। इस प्रकार 7 करोड़ से अधिक व्यक्ति बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 ( MPI ) के अनुसार , " भारत में सबसे गरीब राज्यों के रुप में बिहार , झारखंड एवं उत्तर प्रदेश उभरे हैं। सूचकांक के अनुसार , बिहार में 51.9 % , झारखंड में 42.16 % तथा उत्तर प्रदेश में 37.79 % जनसंख्या गरीब हैं जबकि पश्चिम बंगाल में 37. 79 % जनसंख्या गरीब है। वर्तमान बाजार मूल्य ( 2020–21 ) के अनुसार , बिहार राज्य की जीडीपी 6,79,473 करोड़ रुपए ( US $ 90 बिलियन ) थी। भारत की राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ( NSO ) की रिपोर्ट में बिहार कम साक्षरता दर वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर है। बिहार की समग्र साक्षरता दर 70.9 फीसदी रही जो राष्ट्रीय औसत ( 77.7 फीसदी ) से 6.8 फीसदी कम है। असर (ASER) के 2016 के सर्वेक्षण के मुताबित , बिहार में तीसरी कक्षा के मात्र 18 % छात्र ही शब्दों को पढ़ पाते हैं। 2021–22 के बिहार बजट विश्लेषण के अनुसार , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर 2659 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। किंतु फिर भी बिहार में 33 फीसदी लोग अब भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। संपन्नता को प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य में अवस्थित विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु कई नीतियों व कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया और बिहार की आर्थिक विश्लेषण व सर्वेक्षण इस दिशा में एक सकारात्मक पृष्ठ दिखाने में सफल भी लगती है , किंतु संपन्नता के बाद भी बिहार अभावग्रस्तता का शिकार हो रहा है जिसका कारण संपन्नता का गलत आकलन करना है। गरीबी उन्मूलन के लिए कई प्रकार के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं जिनमें से कुछ कार्यक्रम प्रमुख हैं जो निरंतर सक्रिय रहकर गरीब जनों को लाभान्वित करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। वर्तमान में बिहार में गरीबी की स्थिति भारत के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक भयावह है । बिहार में गरीबी की स्थिति न केवल ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान है बल्कि यह शहरी क्षेत्रों में भी विद्यमान है ।

**शब्द कुंजी** : - बिहार , गरीबी की समस्या , राज्य की भूमिका , गरीबी उन्मूलन।

## परिचय

भारत के प्रमुख राज्यों में से बिहार एक है। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार राज्य के पूर्व में पश्चिम बंगाल , पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित है। इन तीन भारतीय राज्यों के अलावा बिहार के उत्तर में नेपाल है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार , बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 थी जबकि भारत की कुल जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ थी। जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार , 2022 में अनुमानतः बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ होने की है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में तीसरा है। बहुआयामी सूचकांक के अनुसार , बिहार में 51.91 % व्यक्ति गरीब हैं। इस प्रकार 7 करोड़ से अधिक व्यक्ति बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बिहार अपने स्तर से विकास को प्राप्त करने हेतु प्राथमिक , द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्रों में भरपूर योगदान दे रहा है किंतु फिर भी गरीबी की समस्या ने गंभीर रुप को धारण करके विकास की गति एवं मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। राज्य में शिक्षा , स्वास्थ्य , स्वच्छता एवं मौलिक सुविधाओं का अभाव राज्य की जनता की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है , जिसके अनुसार , करोड़ों रुपए खर्च हो जाने के बाद भी बिहार राज्य में गरीबों की संख्या में कमी आने के स्थान पर वृद्धि ही हो गई है। आय के निर्बाध स्त्रोत की प्राप्ति द्वारा ही बिहार में गरीबी की समस्या को कम करके दीर्घकाल में दूर किया जा सकेगा। गरीबी के उन्मूलन का कार्य व्यक्तिगत न होकर सरकार के योगदान की भी आवश्यक्ता है।सरकार के सहयोग एवं नीतियों के कार्यान्वयन के बिना केवल व्यक्तिगत अभ्यास से गरीबी को उन्मूलित करना कठिन एवं असंभव है। गरीबी उन्मूलन में राज्य की भूमिका सर्वोपरि है , क्योंकि राज्य द्वारा ही आर्थिक सहयोग के साथ ही साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है जिसका मूल उद्देश्य कौशल एवं तीक्ष्णता को प्राप्त करके रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना होता है। रोजगार के नवीन अवसर गरीबी की गहनता को समय के साथ कम करते हुए पूर्ण रुप से समाप्त करने में सफल होंगें।

## अध्ययन की विधि

बिहार राज्य में गरीबी की स्थिति के अध्ययन एवं इसमें राज्य की सार्थक भूमिका के अवलोकन हेतु द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है । द्वितीयक स्त्रोतों में पुस्तक , जर्नल , विभिन्न प्रकार की पत्रिका जिसमें इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीक्ली आदि शामिल हैं , का सहयोग प्राप्त किया गया है । साइटों में सरकारी व गैर सरकारी अनेक साइटों का भ्रमण किया गया है । साथ ही साथ शब्दबद्ध के कार्य को संपूर्ण करने हेतु एम० एस० वर्ड के माध्यम का उपयोग किया गया है ।

## साहित्य समीक्षा

"2000 ई० में झारखंड बिहार से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रुप में उदित हुआ। झारखंड राज्य में खनिज संसाधनों की दृष्टि से समृद्धि है , जबकि कृषि उत्पादन में यह गरीब है। 75 प्रतिशत से अधिक कार्यबल कृषि में लगा हुआ है , लेकिन राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 20 प्रतिशत ही उत्पन्न करता है। लगभग 45 प्रतिशत क्षेत्र गैर कृषि उद्योग के अधीन है और 32 प्रतिशत कृषि योग्य अपशिष्ट है जो कृषि उत्पादन के लिए अनुपयुक्त है और केवल 23 प्रतिशत क्षेत्र खेती के अधीन है। झारखंड में गरीबी की घटनाओं का अनुमान 46 प्रतिशत है , हालाँकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 60 प्रतिशत लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। रोजगार के अवसरों की कमी के कारण मात्र एक तिहाई आबादी ही आर्थिक गतिविधियों में लगी हुई है।" (शर्मा के , 2012)

"गरीबी की मात्रा में क्षेत्रीय असमानता के फलस्वरुप भिन्नता पाई जाती है , फलतः भारत के विभिन्न राज्यों में गरीबी की मात्रा भिन्न – भिन्न होती है । उदाहरणस्वरुप केरल में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत 16 है , जबकि बिहार राज्य में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत 81 है ।" (अल्कीरे एवं सैंटोस , 2010)

बर्द्धन पी ० और मुखर्जी डी ० (2004) ने इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली में प्रस्तुत अपने पेपर के माध्यम से पश्चिम बंगाल पंचायत द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों एवं उसके सफल रुप में परिणत करने हेतु भूमि सुधार , कृषि उत्पादकता में वृद्धि , रोजगार कार्यक्रम एवं वित्तीय सहयोग को शामिल किया है। नमूने में 89 गाँव शामिल हैं और इसमें लगातार चार पंचायत प्रशासन शामिल है। गरीबी उन्मूलन के प्रयासों का औसत स्तर ऊँचा था , समय के साथ गाँव से बाहर एवं भीतर दोनों में ही गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में सुधार हुआ। भूमि सुधार से भूमि समान रुप से वितरित हुई साथ ही गरीब लोगों में साक्षरता के स्तर में वृद्धि हुई।

"उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यह गरीब राज्यों में से एक है। हाल के प्रगति के संकेतों के बावजूद , उत्तर प्रदेश अभी भी अपने विभिन्न आर्थिक और गैर – आर्थिक आयामों में गरीबी को कम करने और सभी नागरिकों के लिए सुरक्षा और कल्याण में सुधार करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है । गरीब एक विषम समूह हैं , वे न केवल भौतिक दृष्टि से वंचित हैं , बल्कि उनका मानव विकास भी कम है और वे अनिश्चित और कभी – कभी खतरनाक वातावरण में भी रहते हैं।" (कोजेल वी ० एवं पार्कर बी ० , 2003)

दाण्डेकर ने गरीबी को परिभाषित करने के लिए आय अथवा उपभोग के निश्चित मात्रा को आधार बनाया जिसके द्वारा जीवन के मूलभूत आवश्यक्ता को पूरा किया जा सके। न्यूनतम आय की उपलब्धता गरीबी को मापने का आर्थिक आधार नहीं होती बल्कि गरीबी की गणना में पौष्टिक भोजन , अच्छी शैक्षणिक योग्यता , बेहतर स्वास्थ्य , आवास एवं शौचालय की सुविधा , शुद्ध पेय जल आदि को भी आधार बनाया जाता है। (दाण्डेकर 1981)

गरीबी एवं भूखमरी की समस्या के उन्मूलन केन्द्रित नीतियों का लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यक्ता है । इस संदर्भ में अर्थशास्त्री महबूब - उल - हक का सुझाव है कि " विकास के लक्ष्य को कुपोषण , रोग , अशिक्षा , गरीबी , मलिनता , बेरोजगारी एवं असमानता के क्षेत्र में निरंतर कमी एवं कालांतर में उन्मूलन द्वारा परिभाषित किया जा सकता है । सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि करके गरीबी को कम किया जा सकता है एवं इसके विपरित गरीबी को कम करके सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि किया जा सकता है ।" (महबूब - उल - हक , 1971 , pp6)

"गरीबी किसी भी गरीब व्यक्ति के लिए वास्तविक भय है और यह न केवल गरीब व्यक्ति के लिए भय का कारण है बल्कि यह गैर – गरीब एवं राज्य के लिए भी भय का विषय है । कुछ हद तक गरीब व्यक्ति इस अवस्था के प्रति अभयस्त रहते हैं ।" (एल्मी , 1920)

## बिहार : संपन्न अथवा अभावग्रस्त

बिहार राज्य भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है। बिहार में प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों के साथ ही सेवा क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वर्तमान बाजार मूल्य ( 2020–21 ) के अनुसार , बिहार राज्य की जीडीपी 6,79,473 करोड़ रुपए ( US $ 90 बिलियन ) थी। जिसमें कृषि क्षेत्र का योगदान 24 % , उद्योग क्षेत्र का योगदान 15 % तथा सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक

61 % रहा। बिहार भारत में सब्जियों एवं फलों के शीर्ष उत्पादकों के रुप में जाना जाता है। जौ , मक्का , गेहूँ एवं दालें बिहार की प्रमुख फसलें हैं। फलों में आम , केला , लीची आदि प्रमुख रुप से उत्पादित होते हैं। उद्योग क्षेत्र में कागज , सीमेंट , रसायन , जूट मिलिंग , काँच व पीतल आदि के बर्तन विशेष स्थान रखते हैं। सेवा क्षेत्र में भी बिहार राज्य विकासरत है। बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 में स्थिर मूल्य पर बिहार की विकास दर 10.5 फीसदी है , जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। वर्ष 2019–20 में प्रति व्यक्ति आय 50,735 रुपए वर्तमान मूल्य पर गणना की गई। वर्ष 2019–20 के वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार का कुल राजस्व 1 लाख 53 हजार 408 करोड़ रुपए रहा । राज्य में 2014–18 में व्यक्ति की औसत आयु 69.1 वर्ष थी जो राष्ट्रीय औसत आयु की तुलना में 0.3 वर्ष कम था। 2014 में बिहार राज्य में शिक्षा पर खर्च की दर 17.3 फीसदी थी जबकि स्वास्थ्य पर खर्च की दर 21.4 फीसदी मापी गई। राज्य के विकास हेतु सात निश्चय योजना को प्रारंभ किया गया जिसका मूल उद्देश्य असहाय ,गरीब , बेरोजगार , भूमिहीन , वृद्धजन महिला एवं बच्चों का विकास करना है।

**सारणी 1**

बिहार राज्य की जीडीपी में प्राथमिक , द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र का योगदान ( 2020–21 )

| क्षेत्र | योगदान का प्रतिशत |
|---|---|
| कृषि क्षेत्र | 24 % |
| उद्योग क्षेत्र | 15 % |
| सेवा क्षेत्र | 61 % |

**स्त्रोत :** बिहार बजट विश्लेषण 2022–23

**लेखा चित्र 1**

बिहार राज्य की जीडीपी में प्राथमिक , द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र का योगदान ( 2020–21 )

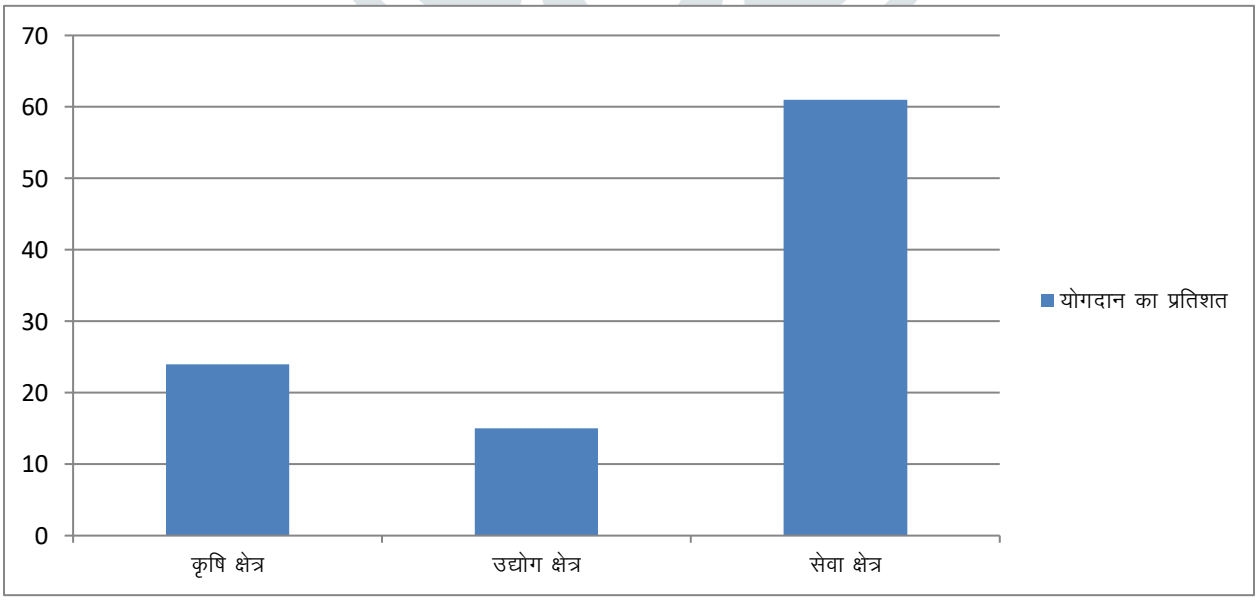


**स्त्रोत :** बिहार बजट विश्लेषण 2022–23

संपन्नता को प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य में अवस्थित विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु कई नीतियों व कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया और बिहार की आर्थिक विश्लेषण व सर्वेक्षण इस दिशा में एक सकारात्मक पृष्ठ दिखाने में सफल भी लगती है , किंतु संपन्नता के बाद भी बिहार अभावग्रस्तता का शिकार हो रहा है जिसका कारण संपन्नता का गलत आकलन करना है। बिहार राज्य अभी भी कई क्षेत्र में अभावग्रस्तता के साथ ही स्वयं को आगे लेकर जा रहा है। बिहार में गरीबी , असमानता , बेरोजगारी , बाढ़ , पूँजी की कमी , महिलाओं का उत्थान आदि कई ऐसे केन्द्र बिंदु पर उठने वाले प्रश्न हैं , जिसका समाधान अभी तक पूर्ण रुप से पता नहीं लगाया जा सका है।

## बिहार में गरीबी की समस्या

बिहार में गरीबी की समस्या वर्तमान समय में उत्पन्न हुई समस्या नहीं है , बल्कि यह कई दशकों से बिहार में विद्यमान है। देश के प्रथम बहुआयामी गरीबी सूचकांक ( MPI ) को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया तथा इसमें बिहार की गरीबी को भी व्यक्त किया गया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार , बिहार देश का सबसे निर्धन राज्य है , जहाँ की 51.91 % आबादी गरीबी की समस्या से जूझ रही है। कुपोषितों की संख्या भी बिहार में सर्वाधिक है। कुपोषण का मूल कारण निर्धनता ही है। धन के अभाव में पौष्टिक भोजन तो उपलब्ध नहीं ही हो पाता है , मात्र दो वक्त का भोजन भी जुटाना गरीब व्यक्ति के लिए चुनौती हो जाती है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार , " गरीबी के मानदंड के 12 प्रकार हैं , जिन्हें शिक्षा , स्वास्थ्य और जीवन स्तर के तीन वर्गों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।" स्वास्थ्य के अंतर्गत पोषण , बाल व मातृ मृत्यु दर , प्रसव पूर्व की देखरेख सम्मिलित है। इसके आधार पर पोषणता का स्तर , शिशु व किशोरों का स्वास्थ्य तथा जीवन प्रत्याशा एवं प्रसव से पूर्व गर्भवती महिलाओं की स्थिति का पता लगाया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत एक बच्चे द्वारा स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों , उनका नामांकन एवं उपस्थिति के आधार पर गरीबी की मात्रा को निर्धारित करना संभव हो पाता है। जीवन स्तर के आधार पर गरीबी की समस्या को ज्ञात करने के लिए स्वच्छता , पेय जल की सुविधा , आवास व शौचालय की सुविधा , खाना पकाने का ईंधन , भोजन में हरी सब्जी व फल इत्यादि की उपस्थिति को आंका जाता है , यदि व्यक्ति के पास इन सुविधाओं का अभाव है तो वह व्यक्ति गरीब है। भारत की राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ( NSO ) की रिपोर्ट में बिहार कम साक्षरता दर वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर है। बिहार की समग्र साक्षरता दर 70.9 फीसदी रही जो राष्ट्रीय औसत ( 77.7 फीसदी ) से 6.8 फीसदी कम है। असर (ASER) के 2016 के सर्वेक्षण के मुताबित , बिहार में तीसरी कक्षा के मात्र 18 % छात्र ही शब्दों को पढ़ पाते हैं। 2021–22 के बिहार बजट विश्लेषण के अनुसार , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर 2659 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। किंतु फिर भी बिहार में 33 फीसदी लोग अब भी गरीबी रेखा से नीचे हैं।

## बिहार के पड़ोसी राज्यों में गरीबी की स्थिति

बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल , उत्तर प्रदेश एवं झारखंड है। इन तीन पड़ोसी राज्यों के अलावा नेपाल राष्ट्र बिहार का पड़ोसी है। गरीबी की स्थिति झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में भी बिहार की भांति ही गहन है , जबकि पश्चिम बंगाल में गरीबी की स्थिति बिहार , झारखंड एवं उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 ( MPI ) के अनुसार , " भारत में सबसे गरीब राज्यों के रुप में बिहार , झारखंड एवं उत्तर प्रदेश उभरे हैं। सूचकांक के अनुसार , बिहार में 51. 9 % , झारखंड में 42.16 % तथा उत्तर प्रदेश में 37.79 % जनसंख्या गरीब हैं जबकि पश्चिम बंगाल में 37.79 % जनसंख्या गरीब है।

बहुआयामी गरीबी में परिवार द्वारा सामना किए गए विभिन्न प्रकार के अभावों को सम्मिलित किया गया है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत के एमपीआई में तीन समान रुप से भारित आयाम , स्वास्थ्य , शिक्षा और जीवन स्तर हैं , जो पोषण , शिशु एवं किशोर मृत्यु दर , प्रसवपूर्ण देखभाल , स्कूली शिक्षा के वर्ष , स्कूल में उपस्थिति , खाना पकाने के ईंधन , स्वच्छता , पीने के पानी , बिजली , आवास , संपत्ति बैंक खाते आदि 12 संकेतकों द्वारा दर्शाए गए हैं।

**सारणी 2**

**बिहार एवं पड़ोसी राज्यों में गरीबी की स्थिति**

| राज्य | गरीबी की स्थिति ( प्रतिशत में ) |
|---|---|
| बिहार | 51.9 % |
| झारखंड | 42.16 % |
| उत्तर प्रदेश | 37.79 % |
| पश्चिम बंगाल | 37.79 % |

**स्त्रोत : नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 ( MPI )**

**लेखा चित्र 2**

**बिहार एवं पड़ोसी राज्यों में गरीबी की स्थिति**

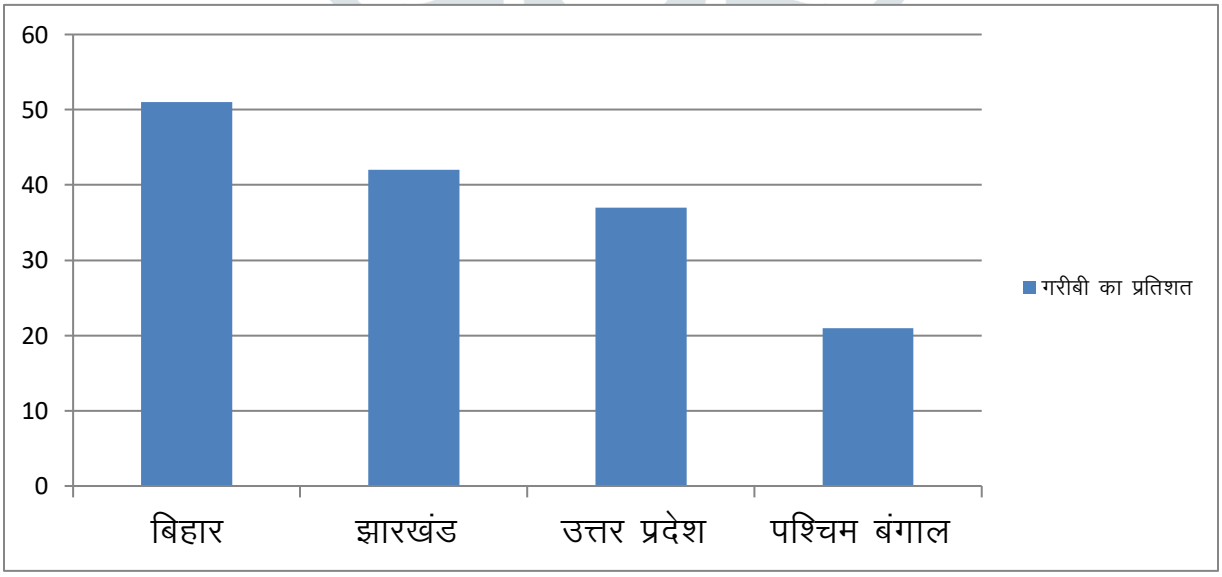


**स्त्रोत : नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 ( MPI )**

## वर्तमान में बिहार में गरीबी

वर्तमान में बिहार में गरीबी की स्थिति भारत के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक भयावह है । बिहार में गरीबी की स्थिति न केवल ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान है बल्कि यह शहरी क्षेत्रों में भी विद्यमान है । गरीबी एवं आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति कृषि क्षेत्र के साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र को भी प्रभावित करती है । गरीबी की अवस्था में प्रति व्यक्ति आय व प्रति व्यक्ति उपभोग दोनों ही कम हो जाते हैं । निष्कर्षतः निवेश एवं रोजगार के पैमाने भी लघु हो जाते हैं और गरीबी की गहनता बढ़ती चली जाती है । वर्तमान में बिहार में गरीबी की मात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है । वर्तमान के कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का आकार बहुत ही वृहद् हो गया है , फलस्वरुप परिव्रजन की प्रक्रिया तेजी से बढ़ने लगी है । यह परिव्रजन गाँवों से शहरों की ओर है । अर्थव्यवस्था की नींव माने जाने वाली कृषि का भी विगत कुछ दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्रों की तुलना में कम हो गया है और इसी समस्या ने ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की समस्या को अधिक गहन रुप प्रदान कर दिया है ।

**सारणी 3**

वर्तमान में बिहार में प्रति व्यक्ति का सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय

( 2014–15 से 2019–20)

| | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शिक्षा , खेलकूद , कला एवं संस्कृति | 1513 | 1724 | 1791 | 2162 | 2404 | 3025 |
| चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य | 330 | 411 | 486 | 538 | 626 | 771 |
| जलापूर्त्ति एवं स्वच्छता | 416 | 407 | 778 | 662 | 1339 | 1746 |
| सामाजिक सेवाएँ | 3055 | 3482 | 3924 | 4355 | 5337 | 6966 |
| आर्थिक सेवाएँ | 2670 | 3358 | 3979 | 3949 | 3561 | 4901 |
| पूँजी परिव्यय | 1661 | 2157 | 2409 | 2517 | 1803 | 3079 |
| सामान्य सेवाएँ | 2577 | 2843 | 2895 | 3146 | 3595 | 4274 |

स्त्रोत : वित्त लेखा एवं राज्य सरकार बजट

## लेखा चित्र 3

वर्तमान में बिहार में प्रति व्यक्ति का सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय

( 2014–15 से 2019–20)

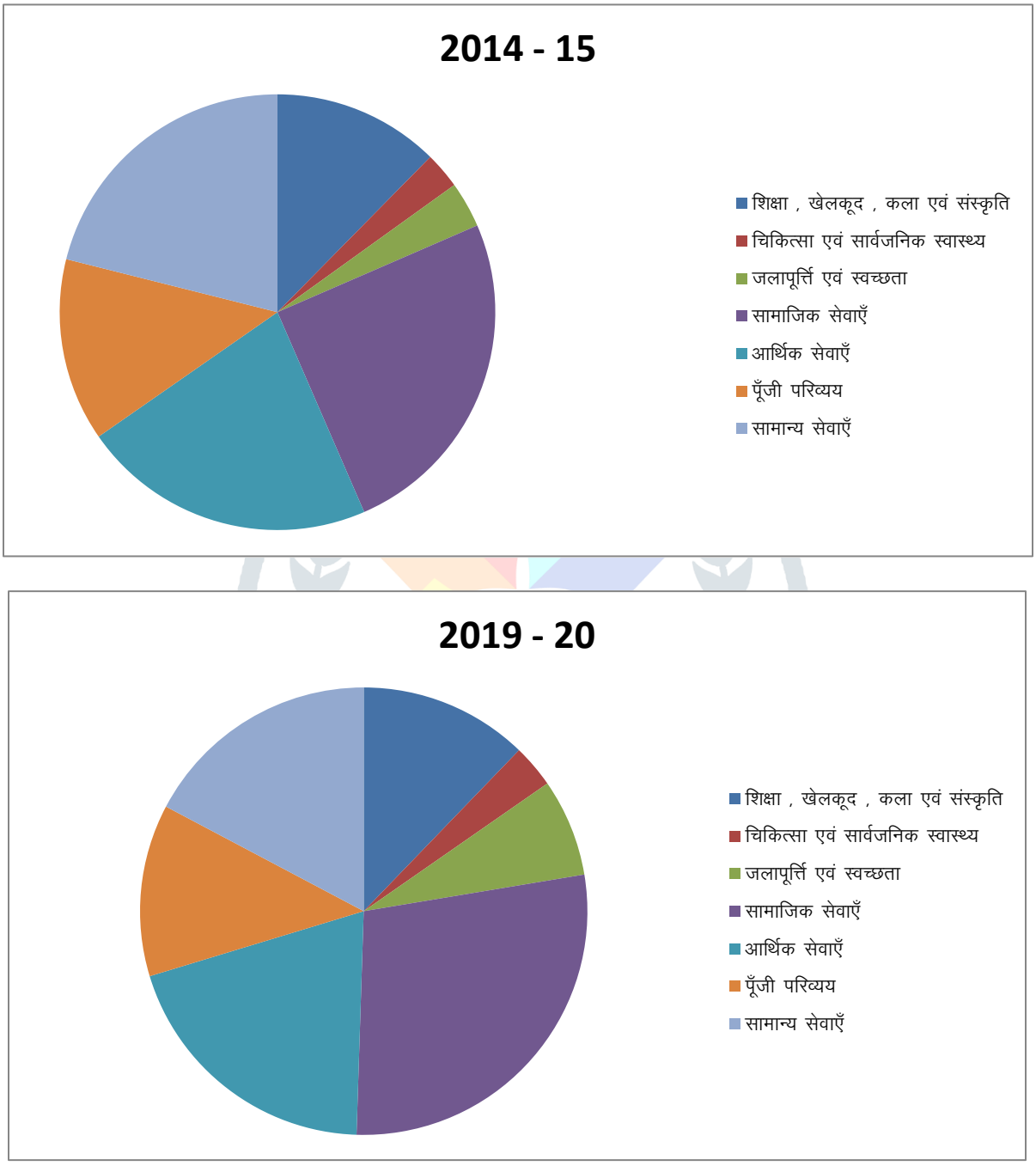


स्त्रोत : वित्त लेखा एवं राज्य सरकार बजट

नीति आयोग के अनुसार , "भारत की कुल जनसंख्या का 25 % गरीब है अर्थात् भारत में हर चौथा व्यक्ति गरीब है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के शामिल 109 राष्ट्रों में भारत का स्थान 66 वाँ है। नवम्बर 2021 में नीति आयोग के द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत का अंक 0.118 था। इसमें शहरी क्षेत्र का अंक 0.08 एवं ग्रामीण

क्षेत्र का अंक 0.155 था। " विश्व गरीबी घड़ी के वास्तविक समय के आंकड़ों के अनुसार , " भारत की 7 % आबादी अत्यधिक गरीबी में जी रही है और 0.6 भारतीय हर मिनट अत्यधिक गरीबी से बचने का प्रयास कर रहे हैं।

**सारणी 4**

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत

| वर्ष | भारत का स्थान | भारत का अंक | शहरी क्षेत्र का अंक | ग्रामीण क्षेत्र का अंक |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 66 वाँ | 0.118 | 0.08 | 0.155 |

स्त्रोत : वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक , 2021

## निष्कर्ष

भारत एक विकासशील राष्ट्र है , जिसमें बिहार प्रमुख राज्यों में से एक है। बिहार की जनसंख्या वर्तमान में लगभग 14 करोड़ है और इसका एक तिहाई भाग गरीबी की समस्या से जूझ रहा है। गरीबी की समस्या ने बिहार के निवासियों के जीवन स्तर को निम्न बना दिया है , साथ ही साथ वे अपनी मौलिक आवश्यक्ताओं को पूर्ण करने में भी असफल हैं। बिहार के साथ ही साथ इसके पड़ोसी राज्य झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में भी गरीबी की समस्या दृष्टिगोचर हो रही है , जबकि बिहार का तीसरा पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल गरीबी की दिशा में बिहार , झारखंड एवं उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर स्थिति में है। गरीबी की समस्या को दूर करने में व्यक्तिगत स्तर पर तो निराकरण का प्रयास किया जाना है , इसी के साथ ही सरकार की सशक्त भागीदारी की भी नितान्त आवश्यक्ता है।

## संदर्भ

1. शर्मा, के ० (2012) , चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ अर्बन पॉवर्टी अ केस स्टडी ऑफ झारखंड (इंडिया)
2. अल्कीरे , एस ० एवं सैंटोस एम ० इ ०, (2010) , बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2010 , ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एण्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटीव ।
3. बर्द्धन पी ० और मुखर्जी डी ० (2004) , पॉवर्टी ऐलिविएशन एफर्टस ऑफ पंचायत्स इन वेस्ट बंगाल , इकोनोमिक एण्ड पॉलिटीकल वीकली , 965 – 974.
4. कोजेल वी ० एवं पार्कर बी ० , (2003) , अ प्रोफाइल एण्ड डायग्नोसटीक ऑफ पॉवर्टी इन उत्तर प्रदेश , इकोनोमिक एण्ड पॉलिटीकल वीकली , 385 – 403 .
5. दाण्डेकर , वी ० एम ० (1981) , ऑन मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी , इकोनोमिक एण्ड पॉलिटीकल वीकली , 16 (30) , 1241–1250
6. उल हक , एम ० (1971) , इंपलोयमेंट एण्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन द 1970's : ए न्यू पर्सपेक्टीव । पाकिस्तान इकोनोमिक एण्ड सोशल रिव्यू , 9(1/2) , 1–9.

7. एल्मी , एफ ० (1920) , द मिनिंग ऑफ पॉवर्टी , द पब्लिक हेल्थ जर्नल , 11 (11) , 516–523.
8. वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक , 2022
9. बिहार बजट विश्लेषण 2022–23
10. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) 2011 – 2012
11. असर (ASER) सर्वेक्षण ( 2016 )
12. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय रिपोर्ट ( NSO ) 2011 – 2012
13. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण , 2021–2022
14. https://prsindia.org/budgets/states/bihar-bihar-analysis-2022-23
15. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक , 2021
16. वित्त लेखा एवं राज्य सरकार बजट , 2021